उ.प्र. की नवीन औद्योगिक नीति निर्धारण हेतु औद्योगिक संगठनों से संवाद शुरू

लखनऊ, 11 जून 2012

उत्तर प्रदेश की नई अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2012 के निर्धारण के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी हितधारक पक्षों की राय को सम्मिलित किए जाने की मंशा को आगे बढ़ाते हुए आज औद्योगिक संगठनों से औपचारिक विचार–विमर्श का दौर शुरू हो गया। इस तीन दिवसीय प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा इस हेतु गठित स्टेयरिंग कमेटी औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से आमने–सामने बैठकर संवाद करेगी।

आज की बातचीत में औद्योगिक संगठनों द्वारा भूमि, अवस्थापना, स्टैम्प ड्यूटी, कर, ऊर्जा, प्रदूषण, वित्त आदि विषयों को विस्तार से उठाया गया। सभी की यह मांग थी कि नीति को लागू करने के लिए समयबद्ध अधिसूचना या शासकीय आदेशों को भी पारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

शासकीय स्टेयरिंग कमेटी के सदस्य सचिव व सचिव–औद्योगिक विकास, संजय प्रसाद ने कहा, "राज्य सरकार नवीन नीति में सभी स्टेकहोल्डरों के प्रगतिशील सुझावों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि अवस्थापना व औद्योगिक विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन हो तथा राज्य का समग्र विकास हो सके।"

विशेष सचिव–अवस्थापना विकास एवं संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, कौश राज शर्मा ने उपस्थित औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि अवस्थापना, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति 2012 को अंतिम रूप देने के पहले विभागों की राय लेने के बाद एक बार फिर से औद्योगिक संगठनों से विचार–विमर्श किया जाएगा।

इण्डियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के महासचिव मनीश गोयल ने हस्तशिल्प क्लस्टर्स व सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं, संयुक्त सुविधा केन्द्रों, डिज़ाइनिंग, परीक्षण व जांच सुविधाओं के प्रविधान किए जाने की मांग की। इसके अतिरिक्त आवासीय व वाणिज्यिक कर से अलग एक 'औद्योगिक कर' की व्यवस्था किए जाने की बात भी की।

प्रोविन्शियल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, कानपुर के महासचिव अतुल सेठ ने लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए संयुक्त उत्प्रवाह शोधन संयत्रों की स्थापना की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किए जाने की मांग की।

सी.आई.आई. (कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इन्डस्ट्री) के उपनिदेशक गजेन्द्र वर्मा ने राज्य में उत्कृष्ठ सड़क, परिवहन व शुष्क पार्ट बनाए जाने का प्रविधान करने के लिए कहा। उन्होंने नये औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत पारेषण व वितरण तंत्र को मजबूत करने की वकालत करते हुए इन क्षेत्रों में नये उपकेंद्रों की स्थापना के प्रविधान करने की तथा उद्योगों के लिए पृथक वैट वर्गीकरण की मांग की।

इनके अतिरिक्त वेस्टर्न यू.पी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, मेरठ के आर. के. जैन तथा ऐसोचैम के आर.सी. वर्मा ने भी कई मुद्दों को उठाते हुए सक्रिय प्रतिभाग किया।

सभी औद्योगिक संगठन इस बात पर एक मत थे कि उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई नीति में समुचित प्राविधान होने चाहिए। औद्योगिक संगठन के साथ सरकार की स्टेयरिंग कमेटी के संवाद के कल और परसों, मंगलवार व बुधवार को अभी दो दौर और होंगे।